भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2512

जिसका उत्तर सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

एनएएफआईएस द्वारा ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण

2512. **श्री राजीव प्रताप रूडी**:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के स्रोतों और वित्तीय समावेशन पर नाबार्ड और अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफआईएस) की भूमिका पर विचार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो ग्रामीण परिवारों की आय, ऋण सुलभता, बीमा और बचत व्यवहार के आंकड़ों सहित एनएएफआईएस 2021-22 के प्रमुख निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या आगामी वर्षों में अनुवर्ती एनएएफआईएस-2.0 सर्वेक्षण आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) ग्रामीण परिवारों में संस्थागत ऋण को बढ़ावा देने और उधार के गैर-संस्थागत स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण जैसी प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति तथा सिंतबर 2024 तक जारी किए गए केसीसी की संख्या और कुल वितरित ऋण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): नाबार्ड ने 28 राज्यों और 02 संघ शासित प्रदेशों (जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख) में संदर्भ कृषि वर्ष 2021-2022 के लिए अपना द्वितीय अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफआईएस 2021-22) आयोजित किया। इस तरह का पहला सर्वेक्षण वर्ष 2016-2017 में आयोजित किया गया था। द्वितीय सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i) **आय** – पांच वर्ष की अवधि के दौरान ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय 57.6% की वृद्धि के साथ वर्ष 2016-17 की 8,059 रुपए से बढ़कर 2021-22 में 12,698 रुपए हो गई।

ii) **ऋण तक सुगमता** – 75% कृषि परिवारों ने 2021-22 में संस्थागत स्रोतों से ऋण लिया जो 2016-17 में 60.50% था।

iii) **बीमा** - कम-से-कम एक सदस्य के पास किसी भी प्रकार का बीमा होने वाले परिवारों का अनुपात वर्ष 2016-17 के 25.5% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 80.3% हो गया।

iv)**बचत**- बचत परिवारों द्वारा की गई वार्षिक औसत वित्तीय बचत 2016-17 में 9,104 रुपये से बढ़कर 2021-22 में 13,209 रुपये हो गई।

नाबार्ड द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एनएएफआईएस सर्वेक्षण किया जाता है।

(घ) से (ङ): सरकार ने ग्रामीण परिवारों के बीच संस्थागत ऋण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण के लिए लक्ष्य, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), मुद्रा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), प्रधानमंत्री विश्वकर्मा आदि जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से वहनीय ऋण तक पहुंच शामिल है।

सितंबर 2024 तक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना, स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी) और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के तहत हुई प्रगति **अनुबंध-I** में दी गई है।

*****

अनुबंध-I

"एनएएफआईएस द्वारा ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण" के संबंध में दिनांक 04.08.2025 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2512 के भाग (घ) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

30 सितंबर 2024 की स्थिति के अनुसार केसीसी योजना के तहत हुई प्रगति

प्रचालनरत खातों की संख्या (वास्तविक में)	कुल बकाया राशि (करोड़ रुपये में)
7,71,70,417	9,98,940

स्रोत: आरबीआई और नाबार्ड

30 सितंबर 2024 की स्थिति के अनुसार एसएचजी- बैंक लिंकेज (बचत और ऋण) - सकल

क्र.सं.	ब्योरा	**संख्या (लाख में)**	**कुल धनराशि (करोड़ रुपये में)**
1	एसएचजी की संख्या (लिंक्ड बचत)	146.73	66,328.11
2	वर्ष के दौरान एसएचजी की संख्या (लिंक्ड क्रेडिट)	26.25	67,040.88
3	एसएचजी की संख्या (बकाया)	68.88	2,47,406.79

स्रोत: नाबार्ड

30 सितंबर 2024 (वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए) की स्थिति के अनुसार प्रमुख बैंक-समूहों द्वारा पीएसएल के तहत संवितरण का ब्योरा (वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए)

बैंक- समूह	**पीएसएल संवितरण (राशि ₹ करोड़ में)**
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	8,63,007.51
निजी क्षेत्र के बैंक	7,01,782.91
विदेशी बैंक	77,407.43
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1,92,621.14
कुल	**18,34,818.99**

स्रोत: आरबीआई और नाबार्ड

******